ज़मीन कहां है?

दिल्ली शहर का हर निवासी यही सवाल पूछ रहा है,''ज़मीन कहां है?'' सरकारी अधिकारी और सम्पन्न वर्ग से कहा जाये कि सामाजिक काम के लिये एक टुकड़ा ज़मीन चाहिये तो उनका भी रोना है,''ज़मीन कहां है?'' मध्यम वर्ग अपना मकान बनाना चाहता है तो वह भी सोचता है,''ज़मीन कहां है?'' और गरीब जब भी अपनी झोपड़ी बचाने की कोशिश करता है तो उसको जवाब मिलता है,''ज़मीन कहां है?''

क्या सचमुच दिल्ली में ज़मीन नहीं है?

आंकड़ों को टटोला जाये तो कुछ और ही तस्वीर सामने आती है। कुल मिला कर राजधानी के पास 148,639 हेक्टेयर (1 हेक्टेयर = 2½ एकड़ या 10,000 वर्ग मीटर) है। इसमें से 1981 तक लगभग एक–तिहाई (48,777 हे.) ''शहरी'' क्षेत्र में आ गया था। उसके बाद, दूसरे मास्टर प्लान में, शहरी क्षेत्र में 24,000 हे. और बढ़ा दिया गया। याने कि 2001 तक प्रदेश की करीब आधी ज़मीन (72,777 हे.) शहर के कब्ज़े में आ गई थी।

इस शहरी ज़मीन में से, अलग अलग समय पर, 40% से 50% रहिवाशी इलाका घोषित किया गया है – याने कि लगभग 32,000 हे.। परंतु दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए) के उपलब्ध प्रकाशनों में 1996 तक केवल 13,000 हे. का ही हिसाब मिलता है जिसका उपयोग घर बनाने के लिये किया गया है। और उस 13,000 हे. में भी करीब 2,500 हे. ऐसे हैं जिन पर दिल्ली की सारी पुनर्वास बस्तियां बनी हैं

इसलिये आंकड़ों से एक दूसरा सवाल पैदा होता है,''19,000 हे. ज़मीन कहां गई?'' पते की बात तो यह है कि 100 घर प्रति हेक्टेयर के मानक के हिसाब से इतनी ज़मीन पर 19 लाख परिवार अपना घर बना सकते थे और हर परिवार को 50 वर्ग मीटर ज़मीन मिलती। जबकि दिल्ली में अभी केवल 6 लाख परिवार झुग्गियों में हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, और 7 लाख परिवार अनधिकृत कालोनियों में। कुल मिलाकर 14 लाख बेघर या ''अवैध'' घर हैं।

इसलिये स्वाभाविक है कि दिमाग में सवाल पैदा होता है कि ''वैध घर और उनकी वैध ज़मीन'' गई कहां??

इस सवाल का जवाब पाने के लिए साझा मंच ने कई बार डी.डी.ए, केन्द्र सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली सरकार, और दिल्ली नगर निगम से पेशकश की है। लेकिन हर दफ्तर और अधिकारी से खाली हाथ लौटना पड़ा है। इसलिये सन 2004 में साझा मंच ने अपने सीमित साधनों के अनुरूप दिल्ली में 11 स्थानों पर सर्वेक्षण किया (नक्शा देखिये)

निर्माण, मोबाइल क्रेश, स्वाति, एक्शन इंडिया, किसलय, चिंतन, जन संघर्ष वाहिनी, और खतरा केंद्र के कार्यकर्ताओं ने इन 11 स्थानों पर मौजूद बस्तियों की ज़मीन को नापा और आस–पास की खाली ज़मीन को भी नापा। साथ में डी.डी.ए के भूमि उपयोग नक्शे से यह भी जानने की कोशिश की गई कि उस ज़मीन का निर्धारित उपयोग क्या था। प्राप्त जानकारी नीचे की तालिका में दी गई है।

क्र. स.	बस्ती का नाम	वर्तमान परिवार	वर्तमान क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	खाली क्षेत्र (वर्ग मी.)	कुल क्षेत्र में सम्भव घर*	निर्धारित भूमि उपयोग
1	बनुवाल नगर	2,330	24,851	59,895	2,119	आवासीय
2	वज़ीरपुर	3,500	45,500	216,750	6,556	औद्योगिक
3	पंजाब गार्डन	27	434	10,000	260	आवासीय
4	कठपुतली कालोनी	3,500	35,100	60,525	2,391	औद्योगिक
5	इंदिरा कैम्प 4, विकासपुरी	450	3,920	15,382	483	आवासीय
6	काली बाड़ी	500	11,970	14,180	654	सार्वजनिक
7	सिमेंट गुदाम	436	6,900	37,500	1,110	सरकारी
8	कनक दुर्गा बस्ती	1,200	25,000	31,250	1,406	सार्वजनिक
9	संजय कैम्प	1,000	5,000	50,800	1,395	आवासीय
10	जौनापुर	2,000	625,000	240,000	21,625	हरित
11	कल्याणपुरी	800	21,750	38,000	1,493	आवासीय

**250 घर प्रति हे. के अनुसार*

सर्वेक्षण से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं:

- हर स्थान पर खाली जगह उपलब्ध है।
- शहर के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में इन स्थानों की गिनती है।
- खाली जगह यदि प्राप्त हो जाये, तो एक स्थान को छोड़ कर, बाकि 10 स्थानों में लोगों के लिये पर्याप्त ज़मीन हैं
- इस ज़मीन पर 25 वर्ग मीटर के प्लाट पर 2 मंजिला मकान बन सकता है।
- सुविधाओं के लिये पर्याप्त ज़मीन बची रहेगी।
- 11 स्थानों में से 5 निर्धारित आवासीय क्षेत्र में हैं, 2 औद्योगिक में, 3 सार्वजनिक और 1 हरित क्षेत्र में।